

इरेडा में विनिवेश को केन्द्र की हरी झंडी

नई दिल्ली, (वार्ता): केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरडीई) में विनिवेश को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में कंपनी में विनिवेश के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने को मंजूरी दी गई। निर्गम के जरिए आईआरडीई की बाजार से तेरह करोड़ नब्बे लाख रुपये जुटाने की योजना है।

सार्वजनिक निर्गम के तहत दस-दस रुपये मूल्य के शेयर जारी किए जाएंगे। यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार शेयरों की बिक्री में खुदरा निवेशकों और आईआरडीई के कर्मचारियों को बुक बिल्डिंग के आधार पर पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी। सार्वजनिक निर्गम के जरिए जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल आईआरडीई अपनी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए करेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि हस्तांतरण: सरकार ने गुजरात

केंद्र के निर्णय

- जुटाई गई पूंजी का उपयोग अपनी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए करेगा इरेडा

अहमदाबाद और वडोदरा को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आठ को छह लेन का बनाने के वास्ते भूमि हस्तांतरण को आज मंजूरी दे दी। फैसले के तहत भारतीय मृदा और जल संरक्षण शोध संस्थान बसाड़ की करीब पांच हेक्टेयर इस भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जाएगा।

कैदियों की स्वदेश वापसी: भारत और सोमालिया की जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों की स्वदेश वापसी का रास्ता साफ हो गया है जिससे उनके सामाजिक पुनर्वास में मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच इस आशय का समझौता करने और उसकी पुष्टि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी।

कोरिया के साथ समझौता: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण कोरिया

के साथ नौ अरब डालर की निर्यात ऋण सुविधा हेतु शुरूआती समझौते पर हस्ताक्षर करने को आज मंजूरी

दे दी। यह निर्यात रिण सुविधा भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रस्तावित है।